समक्ष जेवी गुप्ता जे.

राजिंदर किशोर और अन्य- याचिकाकर्ता।

बनाम

केसर दास और अन्य- प्रतिवादी।

***सिविल पुनरीक्षण 1985 का संख्या* 319**

7 मई 1985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 6, नियम 17 - अपीलीय स्तर पर दलीलों का संशोधन - एक दुकान के कब्जे के लिए मुकदमा प्रतिवादी का तर्क है कि संयुक्त हिंदू परिवार फर्म किरायेदार थी - ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाया और बचाव को खारिज कर दिया - डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गई - लिखित बयान में अपीलीय स्तर पर यह दलील देकर संशोधन की मांग की गई कि परिवार का कर्ता एक संविदात्मक किरायेदार था - प्रतिवादी ने संशोधन की मांग में देरी के कारण के रूप में असावधानी और शिक्षा की कमी का अनुरोध किया - ऐसा संशोधन - क्या अपीलीय स्तर पर अनुमति दी जानी चाहिए - प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत देरी के लिए स्पष्टीकरण - क्या पर्याप्त है।

आयोजित, अपीलीय स्तर पर अपीलीय अदालत द्वारा दलीलों में संशोधन की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अपीलीय अदालत को उन सुविख्यात सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जिनके अधीन दलीलों में संशोधन आम तौर पर दिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, किसी संशोधन को मंजूरी देने

से पहले जिन परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक ऐसे संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को करने में देरी है और यदि अपीलीय चरण में आवेदन किया गया है, तो ट्रायल कोर्ट में इसकी मांग क्यों नहीं की गई। जहां लिखित बयान में संशोधन की मांग के लिए अपने आवेदन में प्रतिवादी द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि यह असावधानी के कारण हुआ था और क्योंकि वह शिक्षित नहीं था और कानून से अच्छी तरह परिचित नहीं था, इसलिए प्रस्तावित दलील पहले नहीं ली जा सकती थी, यदि इस व्यापक दलील को अनुमति दी जाती है, तो व्यावहारिक रूप से हर मामले में प्रस्तावित संशोधन की मांग में देरी को समझाने का सवाल बेमानी हो जाएगा। दलीलों में संशोधन की मांग करने वाले पक्ष को पहले उक्त याचिका पर विचार न करने के लिए केवल असावधानी के अलावा ठोस कारण बताने की आवश्यकता होती है। चूंकि अपीलीय अदालत का अधिकार क्षेत्र और भी सीमित है क्योंकि डिक्री पारित होने के बाद पार्टियों के अधिकार अस्तित्व में आते हैं, इसलिए एक बहुत ही मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए कि जिस याचिका पर अभी विचार करने की मांग की गई है उसे पहले क्यों नहीं लिया जा सका। प्रतिवादी द्वारा पहले ट्रायल कोर्ट में दलील दी गई थी कि यह संयुक्त हिंदू परिवार फर्म थी जो किरायेदार थी। उक्त याचिका पर ट्रायल कोर्ट में हारने के बाद, वह एक नई दलील देना चाहता था कि परिवार का कर्ता हस्तांतरित परिसर पर एक संविदात्मक किरायेदार था। यह दलील उन्हें पहले बहुत रास आई। ट्रायल कोर्ट में हारने के बाद, उन्हें इस विरोधाभासी दलील को अपील में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी मामले में, अपीलीय चरण में लिखित बयान की माफी मांगने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया था।

(पैरा 4)

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका श्री आर. डी. अनेजा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत के 3 जनवरी, 1985 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से याचिका को स्वीकार करते हुए और लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति दी गई, जैसा कि

प्रार्थना की गई थी, विषय दूसरे पक्ष को लागत के रूप में 200 रु रुपये का भुगतान करने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील सी. बी. गोयल,

वी. के. जैन, प्रतिवादी के लिए वकील।

निर्णय

जेवी गुप्ता, जे.

1. वादी- याचिकाकर्ताओं ने गुड़गांव की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित दुकान के संबंध में कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, इस आरोप पर कि इसे मूल रूप से 35 रुपये के मासिक किराए पर किराया नोट, दिनांक 15 जुलाई, 1953 द्वारा उत्तम चंद के पक्ष में किराए पर दिया गया था। जून, 1981 के महीने में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे केसर दास और अन्य, प्रतिवादी, ने उस पर अवैध और जबरन कब्ज़ा कर लिया था। लिखित बयान में दलील दी गई थी कि किरायेदारी मेसर्स उत्तम चंद केसर दास नामक संयुक्त हिंदू परिवार फर्म के पक्ष में थी और किराया नोट उत्तम चंद द्वारा प्रबंधक और कर्ता के रूप में अपनी क्षमता से निष्पादित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप, वादी के मुकदमे को 28 अप्रैल, 1984 के निर्णय और डिक्री द्वारा डिक्री कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर, प्रतिवादियों ने 11 मई, 1984 को अपील दायर की। लंबित रहने के दौरान अपील में, प्रतिवादियों ने 12 सितंबर, 1984 को आवेदन दिया, जिसके तहत उन्होंने लिखित बयान में संशोधन की मांग की। मांगी गई दलील यह थी कि किराया नोट के निष्पादन के बाद अनुबंध के नवीनीकरण से किरायेदारी

का एक नया समझौता अस्तित्व में आया था क्योंकि किराया बढ़ गया था और उनके पिता की मृत्यु के बाद जो एक संविदात्मक किरायेदार थे; किराया महीने-दर-महीने देय होना; उन्होंने किरायेदार का दर्जा हासिल कर लिया था क्योंकि संविदात्मक किरायेदारी वंशानुगत थी। वादीगण की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी किसी भी असंगत याचिका को उठाने की मांग नहीं की थी और इसलिए, वादी पक्ष पर किसी भी तरह का पूर्वाग्रह होने का कोई सवाल ही नहीं था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अनुसार, प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे असावधानी के कारण ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका नहीं उठा सके क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे और कानून से अच्छी तरह परिचित नहीं थे। परिणामस्वरूप, लिखित विवरण में संशोधन हेतु आवेदन की अनुमति दी गई। उसी से असंतुष्ट होकर वादीगण ने यह पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय में दाखिल की है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से ली जाने वाली याचिका में लिखित बयान प्रतिवादियों द्वारा पहले ही लिखित बयान में दी गई दलील के विरोधाभासी है। किसी भी मामले में, विद्वान वकील ने तर्क दिया, आवेदन में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था कि अपील में उठाई गई याचिका को ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं लिया जा सका। तथ्य यह है कि आवेदन अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया था, यह साबित करता है कि यह वास्तविक नहीं था और कार्यवाही में देरी करने के एक गुप्त उद्देश्य से दायर किया गया था। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने *रंजीत कौर* बनाम *अजायब सिंह*[1] पर भरोसा किया। दूसरी ओर,

[1] 1984 आर एल आर 348।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही लिखित बयान के प्रस्तावित संशोधन की अनुमति देने वाला आदेश गलत था, फिर भी पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदन दाखिल करने में देरी संशोधन की अनुमति न देने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रस्तावित याचिका विरोधाभासी नहीं थी और किसी भी मामले में, वास्तविक विवाद का निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक था। पार्टियों के बीच, इसे निचली अपीलीय अदालत ने उचित रूप से अनुमति दी है। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने *रघबीर प्रसाद* बनाम *चेत राम*[2], *बिक्रम दास* बनाम *निरमा सिंह*[3] और *ईश्वरदास* बनाम *मध्य प्रदेश राज्य*[4] पर भरोसा किया।

3. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और प्रतिबंध में उद्धृत मामले के कानून का भी अध्ययन किया है।

4. बेशक, किसी अपीलीय अदालत द्वारा अपीलीय स्तर पर दलीलों में संशोधन की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है, जैसा कि *ईश्वरदास के मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। परंतु साथ ही, इसमें यह भी देखा गया है कि यह आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय को उन प्रसिद्ध सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जिनके अधीन आमतौर पर अभिवचनों में संशोधन दिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, किसी संशोधन को मंजूरी देने से पहले जिन परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक है इस तरह के संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में देरी और, यदि अपीलीय चरण में आवेदन किया

[2] 1971 सी एल जे 612।

[3] 1981(2) आर एल आर 101।

[4] ए आई आर 1979 एस सी 551।

गया है, तो ट्रायल कोर्ट में इसकी मांग क्यों नहीं की गई। मौजूदा मामले में, लिखित बयान में संशोधन की मांग के लिए अपने आवेदन में प्रतिवादियों द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि यह असावधानी से हुआ था और क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे और कानून से अच्छी तरह परिचित नहीं थे, इसलिए प्रस्तावित याचिका नहीं हो सकती थी। यदि इस व्यापक दलील को अनुमति दी जाती है, तो व्यावहारिक रूप से हर मामले में, प्रस्तावित संशोधन की मांग में देरी की व्याख्या करने का प्रश्न बेमानी हो जाएगा। मेरी सुविचारित राय में, दलीलों में संशोधन की मांग करने वाले पक्ष को पहले उक्त याचिका पर विचार न करने के लिए केवल असावधानी के बजाय ठोस कारण देने की आवश्यकता है। चूंकि अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और भी सीमित है क्योंकि डिक्री पारित होने के बाद पार्टियों के अधिकार अस्तित्व में आते हैं, इसलिए एक बहुत मजबूत मामला बनाना होगा कि क्यों याचिका में इसकी मांग की गई और इसे अभी लिया गया और क्यों इसे पहले नहीं लिया जा सकता था। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में निचली अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण गलत, अवैध और गलत धारणा वाला है जिससे न्याय में विफलता हो रही है। प्रतिवादियों द्वारा पहले ट्रायल कोर्ट में दलील दी गई थी कि यह संयुक्त हिंदू परिवार फर्म थी जो किरायेदार थी। उक्त याचिका पर ट्रायल कोर्ट में हारने के बाद, अब वे एक नई दलील लेना चाहते हैं कि उत्तम चंद हस्तांतरित परिसर में एक संविदात्मक किरायेदार थे। यह दलील उन्हें पहले बहुत मिलती थी। ट्रायल कोर्ट में हारने के बाद, उन्हें इस विरोधाभासी दलील को अपील में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी मामले में, प्रतिवादियों द्वारा मंच पर लिखित बयान में संशोधन की मांग करने का कोई मामला नहीं बनाया गया था। जैसा कि पहले देखा गया है, इस संबंध में निचली अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण गलत और अवैध था,

और इस प्रकार उसने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ काम किया है।

5. परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। निर्देश दिया गया है कि अपील का निपटारा कानून के मुताबिक गुण-दोष के आधार पर किया जाए। पार्टियों को निर्देशित किया गया है की 30 मई, 1985 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत में पेश हों।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा